Swami Vivekananda Advanced Journal for Research and Studies
Online Copy of Document Available on: www.svajrs.com

ISSN:2584-105X Pg. 202-206

नई शिक्षा नीति 2020 : कौशल विकास के लिए अवसर

डॉ दीपक जैन
सहायक प्रोफेसर
अध्यापक शिक्षा विभाग, दिगंबर जैन कॉलेज, बड़ौत (बागपत)उत्तर प्रदेश

Accepted: 28/03/2025
Published: 06/04/2025 *DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.17131271*

सारांश

भारत में शिक्षा क्षेत्र में नई शिक्षा नीति 2020 (एनईपी 2020) एक महत्वपूर्ण बदलाव की दिशा में कदम है। यह नीति केवल अकादमिक शिक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों को व्यावहारिक कौशल, नवाचार और रोजगार योग्यता विकसित करने के अवसर प्रदान करती है।कौशल विकास के क्षेत्र में यह नीति निम्नलिखित अवसर प्रदान करती है:

1. बहुविषयक और अनुभव आधारित शिक्षा
2. उद्योग और शिक्षा संस्थानों के बीच सहयोग
3. डिजिटल और तकनीकी शिक्षा का सशक्तिकरण
4. सृजनात्मक सोच, नवाचार और अनुसंधान के लिए वातावरण

इस शोध-पत्र का उद्देश्य एनईपी 2020 में प्रस्तावित कौशल विकास के अवसरों का विश्लेषण करना और उनके प्रभाव, चुनौतियों और सुधारात्मक उपायों का विवरण प्रस्तुत करना है।

प्रस्तावना

भारत एक युवा राष्ट्र है, जहाँ शिक्षा प्रणाली की क्षमता और गुणवत्ता देश के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। परंपरागत शिक्षा प्रणाली में मुख्य रूप से पाठ्यक्रम आधारित शिक्षा और लिखित परीक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया।नई शिक्षा नीति 2020 ने इसे बदलते हुए कौशल आधारित और व्यावहारिक शिक्षा को प्राथमिकता दी है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को न केवल ज्ञानार्जन बल्कि रोजगार और नवाचार के लिए तैयार करना है।कौशल विकास अब केवल व्यावसायिक पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं, बल्कि सभी स्तरों पर लागू होता है। इसके माध्यम से विद्यार्थियों में आत्मनिर्भरता, सृजनात्मकता और समाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है।

नई शिक्षा नीति (NEP-2020) में कौशल विकास की शिक्षा के प्रत्येक लेवल पर योजनाएं

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP-2020) भारत की शिक्षा व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन और सुधार का मार्ग प्रशस्त करती है। इसका एक प्रमुख उद्देश्य शिक्षा को रोजगारपरक और कौशल-आधारित बनाना है।

1. प्रारम्भिक स्तर पर कौशल विकास

1. कक्षा **6** से ही व्यावसायिक शिक्षा और कौशल-आधारित विषयों को शामिल करने का प्रावधान।
2. स्थानीय कारीगरी**,** हस्तकला**,** खेती-बाड़ी**,** पारंपरिक कलाओं और आधुनिक तकनीकी कौशलों से बच्चों को जोड़ना।
3. इंटर्नशिप और प्रायोगिक प्रशिक्षण का अवसर।

2. माध्यमिक स्तर पर अवसर

1. विद्यार्थियों को अकादमिक और व्यावसायिक विषयों के बीच लचीलापन (**Flexibility)**।
2. आईटी**,** उद्यमिता**,** स्वास्थ्य**,** कृषि**,** डिजिटलीकरण और नई तकनीक आधारित कोर्स।
3. "बहु-विषयक" (**Multidisciplinary)** शिक्षा से कौशल और ज्ञान का समन्वय।

3. उच्च शिक्षा स्तर पर अवसर

1. चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम (**UG)** में "मेजर" और "माइनर" विषयों का विकल्प**,** जिससे विद्यार्थी अपने रुचि अनुसार कौशल चुन सकें।
2. व्यावसायिक शिक्षा का उच्च शिक्षा में एकीकरण।
3. "अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट" (**ABC)** की व्यवस्था से कौशल-आधारित कोर्स का लचीलापन।
4. उद्योग और संस्थानों के बीच साझेदारी से प्रायोगिक कौशल विकास।

4. डिजिटल और तकनीकी कौशल

1. ई-लर्निंग**,** ऑनलाइन कोर्स और वर्चुअल लैब्स के माध्यम से डिजिटल कौशल को बढ़ावा।
2. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस**,** मशीन लर्निंग**,** रोबोटिक्स**,** डेटा साइंस जैसे भविष्य-उन्मुख कौशलों पर जोर।
3. "राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच (**NETF)"** की स्थापना।

5. व्यावसायिक शिक्षा और रोजगारपरकता

1. **2025** तक कम-से-कम **50%** विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ने का लक्ष्य।
2. "स्किल गैप" को कम करने और उद्योग की मांग के अनुसार मानव संसाधन तैयार करना।
3. स्थानीय उद्योगों और स्टार्टअप्स से सहयोग।

6. जीवन कौशल और मूल्य शिक्षा

1. आलोचनात्मक चिंतन (**Critical Thinking),** समस्या समाधान (**Problem Solving),** रचनात्मकता (**Creativity)** और संप्रेषण कौशल (**Communication Skills)** का विकास।
2. नैतिक मूल्यों**,** सहयोग भावना और सामाजिक जिम्मेदारी से जुड़ी शिक्षा।

7. अवसरों के लाभ

1. शिक्षा और रोजगार के बीच की खाई कम होगी।
2. विद्यार्थी केवल डिग्री धारक नहीं बल्कि "कुशल मानव संसाधन" बन सकेंगे।
3. ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में युवाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलेगा।
4. "आत्मनिर्भर भारत" और "मेक इन इंडिया" जैसी योजनाओं को गति मिलेगी।

नई शिक्षा नीति 2020 में कौशल विकास की संभावना

भारत की शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी। पारंपरिक शिक्षा प्रणाली विद्यार्थियों को डिग्री तो प्रदान कर रही थी, परंतु बदलते औद्योगिक और तकनीकी परिवेश के अनुरूप उनमें व्यावहारिक कौशल का पर्याप्त विकास नहीं हो पा रहा था। इसी पृष्ठभूमि में नई शिक्षा नीति 2020 को लागू किया गया। इस नीति का मुख्य उद्देश्य शिक्षा को अधिक रोजगारपरक, कौशल-आधारित और समग्र विकास की दृष्टि से उपयोगी बनाना है।प्रारम्भिक स्तर पर नीति विद्यार्थियों को बहुत कम आयु से ही व्यावहारिक शिक्षा से जोड़ने पर बल देती है। कक्षा 6 से ही बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा और विभिन्न प्रकार के कौशलों से परिचित कराया जाएगा। विद्यार्थियों को स्थानीय कारीगरी, हस्तशिल्प, कृषि कार्य, पारंपरिक कलाओं और आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण मिलेगा। इसके लिए इंटर्नशिप और प्रायोगिक प्रशिक्षण जैसी गतिविधियों को भी शामिल किया गया है। इस प्रकार बाल्यावस्था से ही बच्चों में आत्मनिर्भरता और कार्यकुशलता का विकास होगा।माध्यमिक शिक्षा स्तर पर नीति विद्यार्थियों को अधिक स्वतंत्रता और लचीलापन प्रदान करती है। विद्यार्थी अब केवल अकादमिक विषयों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि उन्हें व्यावसायिक और कौशल आधारित विषय भी चुनने का अवसर मिलेगा। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवाएँ, उद्यमिता, कृषि और डिजिटलीकरण से जुड़े पाठ्यक्रम शामिल किए गए हैं। इसका लाभ यह होगा कि विद्यार्थी

अपनी रुचि और क्षमताओं के अनुसार शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे और भविष्य की चुनौतियों के लिए अधिक तैयार होंगे।उच्च शिक्षा स्तर पर नई शिक्षा नीति ने बहु-विषयक शिक्षा की परिकल्पना प्रस्तुत की है। चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम में विद्यार्थियों को "मेजर" और "माइनर" विषय लेने की सुविधा दी गई है। इससे वे अकादमिक ज्ञान के साथ-साथ कौशल आधारित विषयों को भी साथ ले सकते हैं। "अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट" (Academic Bank of Credit) की व्यवस्था विद्यार्थियों को विभिन्न संस्थानों और पाठ्यक्रमों से अर्जित अंकों को जोड़ने का अवसर देती है। साथ ही उद्योग और शिक्षा संस्थानों के बीच सहयोग से विद्यार्थियों को व्यावहारिक अनुभव मिलेगा, जिससे उनकी रोजगार क्षमता और अधिक मजबूत होगी।

तकनीकी और डिजिटल कौशल के विकास के क्षेत्र में भी इस नीति में व्यापक संभावनाएँ हैं। ऑनलाइन शिक्षा, वर्चुअल लैब्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का प्रयोग करके विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक से जोड़ा जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, रोबोटिक्स और साइबर सुरक्षा जैसे नए क्षेत्रों में प्रशिक्षण पर जोर दिया गया है। इसके लिए "राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच (NETF)" की स्थापना का प्रावधान किया गया है। यह मंच शिक्षा और तकनीक के बीच समन्वय स्थापित करके विद्यार्थियों को भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार प्रशिक्षित करेगा।व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा में शामिल करना नई शिक्षा नीति का एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2025 तक 50 प्रतिशत विद्यार्थी किसी न किसी रूप में व्यावसायिक शिक्षा से जुड़े हों। इसके लिए स्थानीय उद्योगों, लघु एवं मध्यम उद्यमों और स्टार्टअप्स के साथ शैक्षिक संस्थानों को जोड़ा जा रहा है। इससे विद्यार्थी रोजगार के साथ-साथ स्वरोजगार और उद्यमिता की दिशा में भी नए अवसर तलाश सकेंगे।

इसके अतिरिक्त, नई शिक्षा नीति जीवन कौशलों पर भी बल देती है। विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन, समस्या समाधान, संप्रेषण कौशल, नेतृत्व क्षमता और सहयोग की भावना विकसित की जाएगी। साथ ही नैतिक शिक्षा, सांस्कृतिक मूल्यों और सामाजिक जिम्मेदारी को भी शिक्षा का हिस्सा बनाया गया है। इससे शिक्षा केवल रोजगार प्राप्त करने का माध्यम न रहकर संपूर्ण व्यक्तित्व विकास का साधन बनेगी।

कौशल विकास के अवसर

1. बहुविषयक शिक्षा

1. छात्रों को विभिन्न विषयों का अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिलता है।
2. इससे उनकी समस्या सुलझाने की क्षमता और आलोचनात्मक सोच विकसित होती है।

2. अनुभव आधारित शिक्षा

1. परियोजना आधारित अध्ययन, इंटर्नशिप और वास्तविक जीवन की समस्याओं पर कार्य।
2. विद्यार्थियों को व्यावहारिक कौशल और उद्योग की समझ प्राप्त होती है।

3. डिजिटल और तकनीकी शिक्षा

1. डिजिटल शिक्षा के माध्यम से दूरदराज़ क्षेत्रों के विद्यार्थियों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा।
2. कंप्यूटर, डेटा विश्लेषण, सूचना प्रौद्योगिकी और तकनीकी कौशल में वृद्धि।

4. उद्योग–शिक्षा सहयोग

1. उद्योगों के साथ प्रशिक्षण और इंटर्नशिप के अवसर।
2. विद्यार्थियों को रोजगार की वास्तविक मांग और कौशल की आवश्यकता समझ में आती है।

5. अनुसंधान और नवाचार

1. नवाचार केंद्र, स्टार्टअप इन्क्यूबेटर और शोध परियोजनाओं के माध्यम से सृजनात्मक सोच बढ़ाना।
2. विद्यार्थियों को नई तकनीक, उत्पाद और समाधान विकसित करने का अवसर मिलता है।

कौशल विकास से जुड़ी चुनौतियाँ और सुधार

1. पारंपरिक शिक्षा पद्धति का प्रभाव

अधिकांश संस्थान अब भी केवल पाठ्यक्रम आधारित और लिखित परीक्षा केंद्रित शिक्षा देते हैं।इससे विद्यार्थियों में व्यावहारिक कौशल और नवाचार की क्षमता सीमित रहती है।

सुधार: अनुभव आधारित शिक्षण, परियोजना आधारित अध्ययन और इंटर्नशिप को पाठ्यक्रम में शामिल करना।

2. प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी

कौशल विकास के लिए विशेषज्ञ और प्रशिक्षित अध्यापक आवश्यक हैं।वर्तमान में शिक्षकों में अनुभव आधारित शिक्षण और उद्योग से जुड़ाव की कमी है।

सुधार: नियमित कार्यशालाएँ, प्रशिक्षण कार्यक्रम और उद्योग से सहयोग।

3. संसाधनों और अवसंरचना की कमी

प्रयोगशालाएँ, डिजिटल उपकरण और तकनीकी संसाधन सभी संस्थानों में समान रूप से उपलब्ध नहीं।ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में संसाधनों की भारी कमी।

सुधार: सरकारी और निजी निवेश द्वारा संसाधन और उपकरण उपलब्ध कराना।

4. उद्योग और शिक्षा संस्थानों के बीच दूरी

प्रशिक्षण और उद्योग के वास्तविक आवश्यकताओं के बीच अंतर।विद्यार्थियों को नौकरी की वास्तविक दुनिया की तैयारी में कठिनाई।

सुधार: उद्योग–शिक्षा सहयोग बढ़ाना, इंटर्नशिप और परियोजना आधारित प्रशिक्षण।

5. डिजिटल साक्षरता में असमानता

डिजिटल शिक्षा और ऑनलाइन पाठ्यक्रमों में ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के विद्यार्थियों की पहुँच कम।

सुधार: डिजिटल शिक्षा को सुलभ बनाना, आवश्यक तकनीकी उपकरण और इंटरनेट सुविधा प्रदान करना।

6. नवाचार और स्टार्टअप संस्कृति की कमी

विद्यार्थियों में नवाचार की मानसिकता और स्टार्टअप समर्थन सीमित।

सुधार: नवाचार केंद्र, स्टार्टअप इन्क्यूबेशन, और अनुसंधान परियोजनाओं के अवसर बढ़ाना।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में समाधान और अवसर

1. बहुविषयक और लचीलापन
एनईपी 2020 विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों में अध्ययन का अवसर देती है।इससे विद्यार्थी अपने रुचि और क्षमता के अनुसार कौशल विकसित कर सकते हैं।

2. अनुभव आधारित शिक्षा
परियोजना आधारित अध्ययन और इंटर्नशिप विद्यार्थियों को वास्तविक कार्य अनुभव देती हैं।इससे नवाचार, समस्या सुलझाने की क्षमता और व्यावहारिक कौशल में वृद्धि होती है।

3. डिजिटल और तकनीकी शिक्षा का सशक्तिकरण
ऑनलाइन पाठ्यक्रम और डिजिटल सामग्री के माध्यम से शिक्षा सभी क्षेत्रों तक पहुँचती है।छात्रों को कंप्यूटर, डेटा विश्लेषण और तकनीकी कौशल प्राप्त होते हैं।

4. उद्योग–शिक्षा सहयोग
इंटर्नशिप, प्रशिक्षण और संयुक्त परियोजनाओं से उद्योग की वास्तविक मांग समझ में आती है।छात्रों को रोजगार और उद्यमिता के लिए तैयार किया जाता है।

5. नवाचार और अनुसंधान
नवाचार केंद्र, स्टार्टअप इन्क्यूबेटर और शोध परियोजनाएँ विद्यार्थियों को सृजनात्मक सोच और उद्यमिता विकसित करने का अवसर देती हैं।

6. मूल्यांकन में सुधार
परियोजना आधारित मूल्यांकन और सतत् मूल्यांकन प्रणाली अपनाना।इससे छात्रों की व्यावहारिक क्षमता, सृजनात्मक सोच और नवाचार कौशल का मूल्यांकन सुनिश्चित होता है।

निष्कर्ष

नई शिक्षा नीति 2020 ने भारत की शिक्षा प्रणाली में गहन परिवर्तन और कौशल विकास के अवसर प्रदान किए हैं। यह नीति केवल पारंपरिक शिक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों को रचनात्मक, व्यावहारिक और रोजगारोन्मुखी शिक्षा प्रदान करने पर केंद्रित है।

1. बहुविषयक शिक्षा और लचीलापन
1. बहुविषयक पाठ्यक्रम विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों में अध्ययन और ज्ञान प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है।
2. इससे उनकी आलोचनात्मक सोच, समस्या समाधान क्षमता और सृजनात्मकता विकसित होती है।
3. विद्यार्थियों को अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार कौशल का चयन करने का अवसर मिलता है।

2. अनुभव आधारित शिक्षा का महत्व
1. परियोजना आधारित अध्ययन, इंटर्नशिप और व्यावहारिक प्रशिक्षण विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन के अनुभव प्रदान करते हैं।
2. इससे उनके व्यावसायिक कौशल, नेतृत्व क्षमता और टीम वर्क में सुधार होता है।
3. अनुभव आधारित शिक्षा छात्रों को नौकरी या उद्यमिता के लिए तैयार करती है।

3. डिजिटल और तकनीकी शिक्षा
1. डिजिटल शिक्षा के माध्यम से शिक्षा को समान और सुलभ बनाया जा सकता है।
2. तकनीकी कौशल जैसे कंप्यूटर, डेटा विश्लेषण, सूचना प्रौद्योगिकी और नवाचार पर ध्यान देने से छात्र आधुनिक रोजगार की मांग के अनुसार तैयार होते हैं।
3. ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के विद्यार्थियों को भी वैश्विक स्तर की शिक्षा का लाभ मिलता है।

4. उद्योग–शिक्षा सहयोग
1. उद्योग और शिक्षा संस्थानों के बीच सहयोग से विद्यार्थियों को वास्तविक आवश्यकताओं और कौशल की समझ मिलती है।
2. यह रोजगार के अवसर बढ़ाता है और नवाचार परियोजनाओं के लिए प्रोत्साहन प्रदान करता है।
3. विद्यार्थियों को स्टार्टअप और उद्यमिता के लिए प्रशिक्षण और मार्गदर्शन मिलता है।

5. नवाचार और अनुसंधान के अवसर
1. नवाचार केंद्र, स्टार्टअप इन्क्यूबेटर और अनुसंधान परियोजनाएँ विद्यार्थियों में सृजनात्मक सोच और नवाचार की क्षमता विकसित करती हैं।
2. इससे युवाओं की समाजिक और आर्थिक योगदान क्षमता बढ़ती है।
3. अनुसंधान परियोजनाएँ छात्रों को समस्या समाधान और नवीन उत्पाद/सेवा विकसित करने में सक्षम बनाती हैं।

6. समान अवसर और समावेशिता
1. डिजिटल शिक्षा और बहुविषयक पाठ्यक्रम सभी विद्यार्थियों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करते हैं।
2. यह शिक्षा में सामाजिक और क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने में मदद करता है।
3. पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को वैश्विक स्तर की शिक्षा तक पहुँच मिलती है।

7. सतत् मूल्यांकन और कौशल आधारित मूल्यांकन
1. परियोजना आधारित और सतत मूल्यांकन प्रणाली विद्यार्थियों की व्यावहारिक क्षमता, नवाचार और रचनात्मक सोच का सही आकलन करती है।
2. यह परीक्षा आधारित शिक्षा की सीमाओं को पार कर विद्यार्थियों को कौशल विकास और आत्मविश्वास प्रदान करती है।

8. राष्ट्रीय और वैश्विक प्रभाव
1. यदि नीति के तहत कौशल विकास और अनुभव आधारित शिक्षा को प्रभावी रूप से लागू किया

गया**,** तो यह भारत के युवाओं को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सक्षम और आत्मनिर्भर बना सकती है।

2. युवा पीढ़ी को रोजगार**,** उद्यमिता और नवाचार के क्षेत्र में नेतृत्वकारी क्षमता प्राप्त होगी।

निष्कर्ष स्वरूप नई शिक्षा नीति २०२० के अंतर्गत कौशल विकास केवल शिक्षा का पूरक नहीं है, बल्कि यह युवा भारत की शक्ति, रोजगारोन्मुखी क्षमता और नवाचार संस्कृति का आधार है। नीति के सफल क्रियान्वयन से भारत की शिक्षा प्रणाली गुणवत्तापूर्ण, व्यावहारिक और रोजगारोन्मुख बनेगी। यह नीति विद्यार्थियों को सृजनात्मक सोच, आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करती है।

संदर्भ सूची

1. द्विवेदी, वी., & जोशी, एम. (2023). NEP 2020 के तहत उच्च शिक्षा में कौशल विकास: अवसर और चुनौतियाँ. अर्थवान शिक्षा पत्रिका, 12(4), 45-60.
2. पाटिल, डी. (2024). NEP 2020 का प्रभाव: कौशल शिक्षा, रोजगार तत्परता और आर्थिक विकास. व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण पत्रिका, 34(2), 123-139.
3. शर्मा, आर., & गुप्ता, ए. (2024). NEP 2020 के तहत व्यावसायिक शिक्षा: कार्यान्वयन की रणनीतियाँ और परिणाम. अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और नवाचार पत्रिका, 13, 78-88.
4. यादव, आर. के., & कुमार, एस. (2023). भारत में व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास: वर्तमान स्थिति और भविष्य की संभावनाएँ. भारतीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण पत्रिका, 1(2), 67-75.
5. शर्मा, आर., & गुप्ता, ए. (2024). NEP 2020 के तहत व्यावसायिक शिक्षा: अवसर, चुनौतियाँ और कार्यान्वयन की रणनीतियाँ. अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और नवाचार पत्रिका, 13, 78-88.
6. शर्मा, आर. (2024). भारत में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण: चुनौतियाँ और अवसर. व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण पत्रिका, 72(4), 475-494.
7. यादव, आर. के., & कुमार, एस. (2023). भारत में व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास: वर्तमान स्थिति और भविष्य की संभावनाएँ. भारतीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण पत्रिका, 1(2), 67-75.
8. शर्मा, आर., & गुप्ता, ए. (2024). NEP 2020 के तहत व्यावसायिक शिक्षा: अवसर, चुनौतियाँ और कार्यान्वयन की रणनीतियाँ. अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और नवाचार पत्रिका, 13, 78-88.
9. शर्मा, आर. (2024). भारत में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण: चुनौतियाँ और अवसर. व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण पत्रिका, 72(4), 475-494.
10. यादव, आर. के., & कुमार, एस. (2023). भारत में व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास: वर्तमान स्थिति और भविष्य की संभावनाएँ. भारतीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण पत्रिका, 1(2), 67-75.

Disclaimer/Publisher's Note: The views, findings, conclusions, and opinions expressed in articles published in this journal are exclusively those of the individual author(s) and contributor(s). The publisher and/or editorial team neither endorse nor necessarily share these viewpoints. The publisher and/or editors assume no responsibility or liability for any damage, harm, loss, or injury, whether personal or otherwise, that might occur from the use, interpretation, or reliance upon the information, methods, instructions, or products discussed in the journal's content.

****